Withholding of foodgrains for National rural employment programme

*188. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

SHRI CHINTAMANI JENA:

Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to 'Hindustan Times' dated 3rd February, 1981 that withholding of foodgrain releases for the National Rural Employment Programme is going to adversely affect the rabi procurement; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) and (b). Foodgrains under national rural employment programme have been released to States keeping in view the availability of foodgrains in the Central pool and the progress made in the utilisation of the quantities already available with the States. As a result of a special review by the Ministry of Rural Reconstruction and the Department of Food the delivery of foodgrains to the States and the Union territories has recently been expedited.

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, मैंने पूछा था कि आने वाली रबी की फसल पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? वास्तविकता यह है कि इन की मिनिस्ट्री के रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत :

"According to the figures available with the Union Ministry of Rural Reconstruction, State Governments utilised up to the end of November this year 9.7 lakh tonnes of foodgrains which is at least 12 lakh tonnes less than the amount utilised last year."

1979 में जो इस्तेमाल किया वह उस से भी कम किया । (व्यवधान) इस में हमारा और आपका कोई सवाल नहीं है । आप वास्तविकता जो है उसको देखें । 1979 की जो बात है :

"Last year, the programme in the food-for-work outfit could generate as many as 49.50 crore mandays by utilising an amount of 43.4 lakh tonnes of grains."

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हालत है इस प्रोग्राम की । इस पर कोई अमल नहीं हुआ । कहते हैं कि फूड ग्रेन्स की कमी है । लेकिन आपने कहा है कि बफर स्टाक में 15 मिलियन टन गेहूं है और 4 मिलियन टन चावल है । जब आप के पास बफर स्टाक में इतना है तब क्या आप 1 मिलियन टन देकर इस प्रोग्राम को लागू नहीं कर सकते हैं जबकि आज कीमतें बढ़ रही हैं और बाजार में गेहूं का भाव ढाई रुपए किलो चल रहा है ? यह सरकार को अपने को मजदूर हितैषी कहती है फिर क्या सरकार अपने स्टाक में से किसानों, मजदूरों के लिए वह अनाज देने पर विचार करेगी ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक किन स्टेट्स में इस कार्यक्रम को अमल में लाया गया है और किन स्टेट्स में नहीं लाया गया है तथा कितनी स्टेट्स में इस प्रोग्राम में मैल-प्रैक्टिसेज पाई गई हैं जहां से इस प्रकार से शिकायतें आई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आनरेबल मेम्बर शायद यह समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जितना चाहे उतना अनाज फूड फार वर्क के लिए एलाट कर सकती है । लेकिन पार्लियामेंट ने इस साल के लिए सिर्फ 340 करोड़ रुपए फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए रखे हैं, उसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं । इसके मुताबिक जितना अनाज हम

ठीक समझते थ देने के लिए उसको हमने तकसीम कर दिया है । बाकी कहीं अगर अनाज की कमी देखी तो उसके मुकाबले में हमने कैश दे दिया । 340 करोड़ रुपया इस फार्मूले के हिसाब से सारी स्टेट्स को बांट दिया गया है । पिछले दिनों में गेहूं के इश्यू में, स्टाक्स को देखते हुए कुछ कमी की गई है ताकि आइंदा दिक्कत न पड़े । उस वक्त कायदा यह बनाया कि तीन किलो से ज्यादा अनाज किसी वर्कर को नहीं दिया जायेगा, एक रोज में, क्योंकि पहले कई स्टेट्स में 5–6 किलोग्राम तक इश्यु किया जाता था । उसमें बचत करने के लिए यह किया गया कि तीन केजी में 2 केजी अनाज और एक केजी के लिए कैश दिया जाएगा । इस हिसाब से जितना भी देना था वह तकसीम कर दिया गया है और अब 1 मिलियन टन फालतू देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, सही तरीके से इस कार्यक्रम पर अमल नहीं किया गया है । मैंने यह भी पूछा था क्या कहीं से मैल-प्रैक्टिसेज की रिपोर्टें आई हैं, और अगर आई हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है । इस में कहीं-न-कहीं शिकायतें आती रहती हैं । जब इतने बड़े देश के अन्दर इतना बड़ा प्रोग्राम चले तो मैल-प्रैक्टिस लोअर-लेबल पर होती हैं,कई जगह पंचायत लेवल पर होती हैं, बी डी ओज लैवल पर भी होती हैं । इस संबंध में जो शिकायतें आती हैं, वे हम स्टेट गवर्नमेंट को रैफर करते हैं, ताकि वे इनकी इन्क्वायरी करा कर हमें इत्तिला दें क्योंकि यह स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की मारफत लागू की जाती हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट डायरैक्टली इसका हिसाब किताब नहीं रखती है । एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रान्त के बारे में पूछता हूं । क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फूड-फार वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने कितना फूड का एलोकेशन किया है और कितना दिया है तथा कितना बाकी है ? क्या उत्तर प्रदेश में जो मैल-प्रैक्टिस होती है, उसकी सूचना आपको मिली है, तथा इस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

MR. SPEAKER: Does this question cover it?

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं हर स्टेट के बारे में यदि माननीय सदस्य चाहें तो जानकारी दे सकता हूं और इस संबंध में एक स्टेटमेंट सारे हिन्दुस्तान का मैं रखने के लिए तैयार हूं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें ।

राव वीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश का मैं बता देता हूं ।

MR. SPEAKER: Please lay it on the table of the House.

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत 78–79, 79–80, 80–81 में फूड-फार-वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितना अनाज आवंटित किया गया था और क्या सरकार इस योजना को खत्म करने जा रही है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : फूड-फार-वर्क का कार्यक्रम तो फिर पांच साल के लिए अपना लिया है और योजना को खत्म करने का तो कोई सवाल नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 78–79, 79–80, 80–81 में आपने कितना अनाज फूड-

फार-वर्क के तहत एलोकेट किया है और जो आपने दिया है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है—आप उसकी फीगर बतलाइये ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जितना पार्लियामेंट ने वोट किया है, उस हिसाब से हमने दिया है । मैं अन्दाजन बता सकता हूं, मुझे उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे । इन्होंने पिछले साल 1979–80 के बारे में पूछा है, पिछले साल इस कार्यक्रम के तहत 28 लाख टन तकसीम किया गया था और इस साल करन्ट ईयर में, 1980–81 में कोई 21 लाख टन के करीब एलाटमेंट हुआ है ।

श्री राम विलास पासवान : आप 1978-79 के बारे में बताइए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस संबंध में आप अलग से सवाल कर लीजिए । यह सवाल इस सवाल से पैदा नहीं होता है ।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आपने छः लाख टन तो कम कर दिया ।

श्री कमला निवास मधुकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पिछले सालों में बहुत सारी स्कीमें ली गई और वे स्कीमें अधूरी रह गई और आपने अन्न सप्लाई नहीं किया । इसलिए उन स्कीमों का क्या हुआ जो अन्न के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जो स्कीमें अधूरी रह गई हैं इस प्रोग्राम के तहत, यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो आगे उसको पूरा करा सकती हैं और नहीं तो अपने फण्ड से भी पूरा किया जा सकता है । इस प्रोग्राम के अन्दर यह कोई गारन्टी नहीं है कि कोई स्कीम अगर अपना ली जाएगी तो उसका सारा खर्च 100 प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी ।

एक दूसरी गलतफहमी माननीय सदस्य की है कि इस साल छः लाख टन अनाज कम कर दिया । उनकी इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहूंगा । सन 1979–80 के अन्दर कैश कम्पोनेन्ट नहीं था और इस साल 21 लाख टन अनाज दिया गया है जिसमें पिछले वर्षों का शेष 7 लाख टन अनाज भी शामिल है, तथा इसके साथ-साथ 70 करोड़ रु० कैश कम्पोनेंट के लिए भी है । इस तरह से हिसाब लगायें तो यह सब पिछले साल से कम नहीं है ।

चौधरी मुलतान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि अनाज की कमी की वजह से रूपया दिया गया था । तो रुपये से तो वह ढाई रु० किलो में खरीदेगा और जो आप अनाज देंगे वह सवा रु० में देंगे, इस तरह से मजदूरों को तो दुगुना नुकसान हो रहा है । दूसरी बात यह है कि आपके पास जितने गोदाम हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और भरे हुए हैं तथा नई फसल भी आने वाली है, लेकिन गोदामों में जगह नहीं है । इस वक्त गल्ला ढाई रु०, दो रु० और कहीं-कहीं पर तीन रु० किलो भी बिक रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन गोदामों को खाली करके और नई फसल के रखने के बारे में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (एच द्वारा जारी)

राव वीरेन्द्र सिंह : अनाज का जितना स्टाक रखने की हमारी नीति है, उस हिसाब से हमारे स्टाक में अभी काफी कमी है । इसलिये हम अनाज खरीदने में कोई कोताही नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद कर हमारा बफर स्टाक जितना कम हुआ है उसको पूरा करना चाहते हैं । इसलिये इसमें आप को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये ।

PROF. MADHU DANDAVATE: In this very House, the hon. Minister while replying to a question regarding

the supply of food for the Food for Work Programme in Bengal, had informed the House that proper accounts regarding the amount utilized were not given; and as a result of that, fresh stocks of foodgrains could not be sent to Bengal. After that, the Chief Minister of West Bengal had also come out with a public statement clarifying the position. I want to know whether that controversy has been sorted out, and whether adequate amount of foodgrains are being made available to the West Bengal Government for the Food for Work Scheme.

RAO BIRENDRA SINGH: So far as we are concerned, there is no controversy; but if the controversy exists or persists in West Bengal, I cannot reply to that question.

PROF. MADHU DANDAVATE: The controversy is from both the sides.

RAO BIRENDRA SINGH: We stick to the information that we have. We have again and again reiterated that the figures supplied by me are correct; and the hon. Speaker has also looked into them. Even now, according to our records, West Bengal, upto December 1980, had a balance of nearly 1 lakh tonnes of foodgrains unutilized.

Scheme to Educate Farmers on change in Crop Pattern

*189. SHRI A. C. DAS: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to introduce schemes to educate the farmers' community on changing the crop pattern and to maximise the benefits from irrigation;

(b) if so, whether such schemes are going to be introduced in Orissa;

(c) the names of these schemes and when they are going to be introduced; and

(d) the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR (RAM): (a) to (d). Government is fully conscious of the need to educate the farmers on changing cropping pattern for maximising benefits from irrigation. Towards this end various schemes have been in operation in Orissa State since November, 1968. More recently in 1977, the new Extension System (Training and Visit) has been introduced in this State, which is called the Orissa Agricultural Development Project. The object of this scheme is to transfer technoloy to farmers both in the irrigated and in the non-irrigated areas for changing the cropping pattern for maximising crop production.

SHRI A. C. DAS: I would like to know from the hon. Minister: what are the various schemes being implemented in Orrissa? Secondly, keep in view the fact that a major portion of our land is dependent on rain water, does Government have any scheme to utilize the rain water, and to educate the farming community to change cropping pattern?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (RAO BIRENDRA SINGH): The Orissa Agricultural Development project has been continuing ever since 1977, and various schemes for training of farmers and to transfer technology to the farmers level for changing the cropping pattern have been going on. I do not know what the hon. Member wants to know with regard to the rain-fed areas; but that is also part of the programme as to how far cultivation can be intensified not only in irrigated areas, but also in rain-fed areas. That is part of the whole scheme.

SHRI A. C. DAS: What happens is that our farmers are not educated on how to utilize the rain-fed water. Actually, what we need there is this; they are doing their own pattern of cultivation. In this context, is Government planning any new form of schemes to be introduced in these areas,